



@swatantraprabhatmedia
@swatantramedia
RNI.No. (UJIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com)
@SwatantraPrabhatonline
news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 08 अप्रैल 2025

वर्ष 16, अंक 83, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

असम में डबल इंजन सरकार को खींचने के लिए एथी-महारथियों के उमड़ी भीड़...04

हमारे पास बीजों का पर्याप्त स्टॉक... ईरान-अमेरिका जंग के बीच सरकार का किसानों को भरोसा

ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे जंग के बीच भारत सरकार ने कहा कि भारत के पास आने वाले बुआई के मौसम के लिए काफी बीज स्टॉक मौजूद है। एडिशनल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर और किसान कल्याण, मनिंदर कौर द्विवेदी ने वेस्ट एशिया में हाल के डेवलपमेंट पर सरकार की इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत के पास आने वाले बुआई के मौसम के लिए काफी बीज स्टॉक मौजूद है। देश में बीजों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के अलावा ICAR और पब्लिक सेक्टर का सपोर्टेड एक सेल्फ-रिलायंट बीज सिस्टम है। किसी भी पॉसिबल रुकावट को पूरा करने के लिए सभी स्टेज (सर्टिफाइड, फाउंडेशन, हाइब्रिड बीज) पर काफी बीज और ब्रीडिंग मटीरियल के साथ एक मजबूत पाइपलाइन भी मौजूद है। खरीफ सीजन 2026 के लिए, सरकार ने लगभग 19.29 लाख क्विंटल सरप्लस के साथ एक आरामदायक बीज अवेलेबिलिटी की स्थिति बताई। द्विवेदी ने बताया कि देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को 166.46 लाख क्विंटल की जरूरत है, जबकि देश में 185.74 लाख क्विंटल अवेलेबल है। इसके अलावा, रबी सीजन के बीज के इनपुट भी मौजूद हैं। द्विवेदी ने कहा, 'सभी एग्री कम्प्लेटीज के होलसेल प्राइस के लिए प्राइस सिचुएशन पर भी नजर रखी जा रही है। मोटे तौर पर, वे नॉर्मल रेंज में हैं, जैसा कि वे पिछले कुछ



सालों से रहे हैं। टॉप क्रॉप, टमाटर, प्याज और आलू के प्राइस रेंज में हैं और होलसेल लेवल पर बेहतर ट्रेड के साथ उनमें सुधार दिख रहा है।

LPG-PNG के अलॉटमेंट को प्राथमिकता

ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल की चल रही लड़ाई के बीच, सरकार ने मक्के के बीज सुखाने के लिए LPG/PNG के अलॉटमेंट को प्रायोरिटी दी है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई भी पक्का किया है। फर्टिलाइजर की सिचुएशन स्टेबल है। सरकार ने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए देश के पास ओपनिंग स्टॉक के तौर पर काफी फर्टिलाइजर है। खरीफ 2026 के लिए राज्यों के साथ सलाह-मशविरा करके भारत की खाद की जरूरत 390.54 LMT आंकी गई है, जिसमें से 180 LMT (46%) ओपनिंग स्टॉक के तौर पर उपलब्ध है। केंद्र ने 30 मार्च को

के अलावा, भारत में आने वाले खेती के मौसम के लिए जरूरी पेस्टिसाइड और दूसरे एग्रीकैमिकल भी काफी मात्रा में मौजूद हैं। सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र राज्यों और UTs के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और इसके लिए हर हफ्ते मॉनिटरिंग कर रहा है। अप्रैल-फरवरी 2026 के दौरान, देश में 2,61,099 MT पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन हुआ। कुल अनुमानित डिमांड 74,266 MT है, जिसमें से खरीफ 2026 में 42,000 MT की जरूरत है।

नकली या मिलावटी पेस्टिसाइड पर कार्रवाई

अफवाहों और गलत तरीकों को देखते हुए, केंद्र ने मल्टी-स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन अप्रोच में नकली या मिलावटी पेस्टिसाइड पर कार्रवाई करने की भी कोशिशें शुरू की हैं। यह राज्यों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) पर भी फोकस कर रहा है। सरकार बायोपेस्टिसाइड्स और सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा दे रही है, और किसानों की जागरूकता और निगरानी, पेस्ट सर्विलांस को बढ़ाने और सटीक सलाह देने की कोशिश कर रही है। द्विवेदी ने बताया कि एग्री कम्प्लेटीज की कीमती काफी हद तक स्थिर हैं और उन पर करीब से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की कीमतों एक रेंज में हैं और तीनों की कीमतों में थोड़ा सुधार दिख रहा है।

घर में नमाज पढ़ने से जुड़ी याचिका, H C ने कहा- चालान वापस ले पुलिस; याचिकाकर्ता का भीड़ नहीं जुटाने का वादा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल बुधवार को नमाज से जुड़े एक मामले का निपटारा कर दिया। बरेली के रहने वाले एक शख्स की ओर से अपने घर में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नमाज के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटाना सही नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता ने भी वादा किया कि विवादाित स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को याचिकाकर्ता तारिक खान और अन्य लोगों के खिलाफ 16 जनवरी, 2026 को जारी किए गए पुलिस चालान को तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया। तारिक के रिश्तेदार हसन खान की संपत्ति पर नमाज अदा की जा रही थी, जिसके लिए पुलिस ने चालान काट दिया था।

कोर्ट ने अवमानना नोटिस किया

जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने 25 मार्च को दिए अपने आदेश में कहा, 'आगर याचिकाकर्ता अपने वादे का उल्लंघन करता है, उसकी संपत्ति पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाता है और इस वजह से क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर असर पड़ता है, तो अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।' साथ ही कोर्ट ने



बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को जारी अवमानना नोटिस भी रद्द कर दिया। दोनों अधिकारी पिछले महीने 25 मार्च को पूर्व आदेश के अनुपालन में हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए और अपने हलफनामे दाखिल किए।

वादा तोड़े को कार्रवाई करे

प्रशासन: H C

इससे पहले हाईकोर्ट ने 11 मार्च के अपने निर्देश के तहत हसीन खान को दी गई सुरक्षा तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया था। हसीन ने अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके परिवार और संपत्ति की सुरक्षा की जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि हसीन खान सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहा है और उनकी संपत्ति पर रोजाना कम से कम 50 से 60 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने इस दावे की पुष्टि के लिए हलफनामों के साथ लगाई गई संपत्ति की कई तस्वीरें भी रिपोर्ट पर रहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरह की परंपरा आगे

जारी रहने दी गई, तो यह क्षेत्र की शांति-सुव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि अगर कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना बनती है, तो राज्य अधिकारियों के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

याचिकाकर्ता की सुरक्षा भी वापस

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के वकील के इस वादे को रिफाईर कर ले लिया कि वे संपत्ति पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने नहीं देंगे। बेंच ने यह भी कहा, हमें आशा और विश्वास है कि याचिकाकर्ता अपने वादे का पूरी तरह से पालन करेगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को इस दलील पर भी ध्यान दिया कि हसीन को अब किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं रह गई, जिसका बाद कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता को दी गई सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने तारिक की ओर से दाखिल रिट याचिका रद्द कर दी।

संक्षिप्त खबरें

MP महिला कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा ! इन्हें मिली जिम्मेदारी, जीतु पटवारी ने दी बधाई



मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस नई कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों और वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए संगठनात्मक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यकारिणी में शामिल नेताओं को महिला सर्वाधिकरण, सामाजिक न्याय और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह नियुक्तियां काफी अहम हैं। महिला कांग्रेस की नई टीम बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि संगठन में सक्रियता, समर्पण और प्रदर्शन के आधार पर ही जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे कांग्रेस को भविष्य में चुनावी लाभ मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह नियुक्तियां काफी अहम हैं। महिला कांग्रेस की नई टीम बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि संगठन में सक्रियता, समर्पण और प्रदर्शन के आधार पर ही जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे कांग्रेस को भविष्य में चुनावी लाभ मिल सके।

'घायल हूं इसलिए घातक हूं... झूठ को बेनकाब किया जाएगा', राघव चड्ढा ने आप नेताओं के आरोपों पर दी सफाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी है। फेसबुक पर लाइव आकर चड्ढा ने एक-एक करके सभी आरोपों का जवाब दिया है और यह स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और चुनिंदा हैं। इनका मकसद संसद में उनकी आवाज को दबाना है। चड्ढा ने कहा कि भेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। पहले मुझे लगा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर तीन बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि जब विपक्ष सदन से वाकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। ये सर्रासर झूठ है। एक दिन ऐसा बताया जाए जब विपक्ष ने वाकआउट किया हो और मैंने उनका साथ न दिया हो। संसद में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आप उसकी फुटेज निकालकर दिखा



दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह हमेशा से विपक्ष के साथ रहे हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। साथ ही सत्ता पक्ष से सवाल भी किए हैं।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले में सारा दोष उन पर ही क्यों?

राघव ने कहा कि उन पर दूसरा आरोप लगाया गया कि 'मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने वाली याचिका पर साइन नहीं किए। ये आरोप सर्रासर गलत है। उन्हें आप के किसी नेता ने इस याचिका पर साइन करने के लिए नहीं कहा। साथ ही राज्यसभा में पार्टी के दस सांसद हैं, जिनमें से छह या सत्त सांसदों ने

खुद ही इस याचिका पर साइन नहीं किया। अब इसमें मेरी क्या गलती है। सारा दोष उन पर ही क्यों। इस याचिका के लिए राज्यसभा में केवल 50 साइन चाहिए थे यानी 105 विपक्षी सांसदों से 50 से ये याचिका पूरी हो जाती।'

ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए हर मुद्दे उठाए

चड्ढा ने कहा कि तीसरा आरोप जो उन पर लगाया गया वो ये था कि वो डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। 'मैं बता दूँ कि मैं संसद में चीखने चिल्लाने, गाली देने या माइक तोड़ने नहीं गया। मैं वहां जनता के मुद्दे उठाने गया हूँ, मैंने कौन से मुद्दा नहीं उठाए। जीएसटी से लेकर पानी तक, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा की बात की। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे उठाए। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए मैं संसद में इंपेक्ट क्रिएट करने गया हूँ, हा हा बात कहता हूँ जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ.'

गैर-जमानती वारंट पर IO को सस्पेंड करना भारी पड़ा: हाईकोर्ट ने बस्ती एसपी को दी अवमानना की चेतावनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक जांच अधिकारी को निलंबित किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना करार दिया। बता दें, यह मामला उस समय सामने आया, जब जांच अधिकारी ने आरोपियों की पेशी सुनिश्चित कराने के लिए गैर-जमानती वारंट प्राप्त किया था। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि एसपी द्वारा जारी निलंबन आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2, बस्ती के आदेश की अवहेलना जैसा प्रतीत होता है। मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी के आवेदन पर विचार कर वारंट जारी किया था।

मामला रत्नेश कुमार उर्फ राजू शुक्ला की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जैसे ही जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ गैर-



जमानती वारंट के लिए आवेदन किया, उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पहले ही एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि किन परिस्थितियों में यह कार्रवाई की गई और अब जांच कौन कर रहा है। हालांकि 2 अप्रैल को दाखिल हलफनामा अदालत को संतोषजनक नहीं लगा।

याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया कि जांच अधिकारी को इस आधार पर निलंबित किया गया कि उसने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए बिना गैर-जमानती वारंट हासिल किया। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि गैर-जमानती वारंट जारी करना अदालत का



लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ के 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'अदय्य साहस, अग्रिम शौर्य एवं उकृष्ट सुशासन के प्रतीक, 'हिंदवी स्वराज' के संस्थापक, राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन।' उन्होंने कहा, 'मातृभूमि की रक्षा और सनातन संस्कृति के गौरव की पुनःस्थापना के लिए उनका समर्पण जीवन और उच्च आदर्श हम सभी के लिए महान प्रेरणा हैं।' उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। अद्वितीय वीरता, दूरदर्शी नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन 'राष्ट्रधर्म' के जीवंत आदर्श के रूप में हमें निरंतर साहस और कर्तव्यपथ पर दृढ़ रहने को प्रेरणा देता है।' उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर अपने स्देश में कहा, 'सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, राष्ट्र के गौरव और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन।' छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था।

भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में क्लीन चिट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पंचकूला के AJL (Associated Journals Limited) प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को भी इस मामले में आरोपमुक्त किया गया है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर आरोप तय करने के आदेश रद्द किए थे, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। ये मामला पंचकूला के सेक्टर-6 में करीब 3,360 को वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा था। इस केस में जांच एजेंसी का आरोप था कि ये प्लॉट कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को दिया गया था। इससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था।



किया कि बिना मजबूत आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर आरोप तय करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अब पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज ये राहत मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे न्यायापालिका पर भरोसा है।

क्या है पूरा मामला?

पंचकूला के सेक्टर-6 में 3,360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड आवंटित करने के मामले में सीबीआई ने हुड्डा समेत एचएसवीपी के चार अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था। हुड्डा पर आरोप था कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया। सीबीआई ने 27 जनवरी 2017 को केस दर्ज किया था। फिर 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दायर की थी।

फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मेडिकल स्टोर मालिक को धमकी फिर शूटआउट की थी प्लानिंग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बटाला पुलिस ने डेरा बाबा नानक में एक मैडीकल स्टोर के मालिक से फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मैडीकल स्टोर पर गोलियां चलाने की साजिश रच रहे 2 युवाओं को पिस्टल और जिंदा रॉड सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एस.एस.पी. बटाला ड. महताब सिंह ने बताया कि डेरा बाबा नानक में एक मैडीकल स्टोर के मालिक को 29 मार्च को एक समाजविरोधी तत्व द्वारा फोन करके उनसे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी जिस संबंधी पुलिस द्वारा थाना डेरा बाबा नानक में केस भी दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हेतु पुलिस



टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नोइस पुत्र नजीर मसीह निवासी पड़ोस के टाहली साहिब और राजविन्द सिंह उर्फ राजा पुत्र भूपिन्द सिंह निवासी तरसिका हाल जिस संबंधी पुलिस द्वारा थाना डेरा बाबा नानक के क्षेत्र में मैडीकल स्टोर पर गोलियां चलायीं हैं और इनके पास हथियार भी हैं।

विदेशी हैंडलर के इशारे पर चलने वाली थी गोली

उन्होंने कहा कि बटाला पुलिस ने उक्त युवाओं को वारदात करने से पहले ही पिस्टल और जिंदा रॉड सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पृच्छाछ के दौरान उक्त युवाओं ने बताया कि उन्होंने डेरा बाबा नानक में एक मैडीकल स्टोर पर गोलियां चलानी थी, यह वारदात विदेश में बैठे समाज विरोधी तत्व के कहने पर करनी थी और उसने ही उनको हथियार मुहैया कराया था। एस.एस.पी. ने कहा कि फिलहाल पुलिस द्वारा उक्त युवाओं को माननीय अदालत में पेश करके इनका रिमांड हासिल किया जा रहा है और इनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

सम्यक्त्व के भाव जागृत हों, आत्म-जागरण, समत्व और सच्चे दर्शन की ओर एक गहन यात्रा

मनुष्य जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पहचान और उसके वास्तविक स्वरूप की खोज का माध्यम है। जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे सत्य को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी संसार में भटकता रहता है। सम्यक्त्व, अर्थात् सम्यक् दर्शन, इस आत्म-जागरण की प्रथम सीढ़ी है। यह वह अवस्था है, जहाँ से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है और जीवन का सच्चा उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है।

जैसे सागर का जल ऊपर से खारा प्रतीत होता है, परंतु गहराई में उतरने पर वही जल मधुर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार दर्शन का विषय भी प्रारंभ में सामान्य व्यक्ति को नीरस या कठिन लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे साधक इसकी गहराई में उतरता है, उसे इसमें आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है, जो आत्मा को स्थिरता और संतोष प्रदान करता है।

सम्यक्त्व का अर्थ केवल किसी सिद्धांत को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक ऐसी जागृत अवस्था है, जहाँ मिथ्यात्व अर्थात् गलत दृष्टिकोण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब सम्यक् दर्शन आत्मा में प्रकट होता है, तब वह सूर्य के समान प्रकाशित होता है, जिसके सामने अज्ञान रूपी अंधकार टिक नहीं पाता। यह स्थिति सहज नहीं होती, बल्कि इसके लिए आत्म-पुरुषार्थ, साधना और निरंतर प्रयास आवश्यक है।

आज के समय में मनुष्य बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों में इतना उलझ गया है कि वह अपने

वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। वह अपने शरीर, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान बैठता है। यही आसक्ति उसे सत्य से दूर ले जाती है। यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले इस देह और संसार के प्रति अत्यधिक मोह को त्यागना होता। जब तक मनुष्य अपने भीतर वैराग्य और समत्व की भावना विकसित नहीं करता, तब तक वह आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकता।

सम्यक्त्व कोई बाहरी वस्तु नहीं है, जिसے किसी से प्राप्त किया जा सके। यह तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जो अज्ञान के कारण दबा हुआ है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, तब यह गुण अपने भीतर हो जाता है। इसके लिए किसी बाहरी आडंबर, दिखावे या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची साधना और आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

आत्म-विश्वास इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण आधार है। बिना आत्म-विश्वास के कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जीवन में मित्र और शत्रु दोनों मिलते हैं, परंतु जिसका आत्म-विश्वास दृढ़ होता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलित और स्थिर रहता है।

इतिहास और धर्मग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ आत्म-विश्वास और सम्यक् दृष्टि के कारण व्यक्तियों ने असंभव को

संभव कर दिखाया। यह आत्म-विश्वास ही वह शक्ति है, जो मनुष्य को कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य अपने भीतर इस शक्ति को जागृत कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि स्वयं अपने जीवन का निर्माता बन जाता है।

समत्व की भावना भी सम्यक्त्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन में सुख और दुःख, लाभ और हानि, मान और अपमान आते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है, वही सच्चा साधक है। जब मनुष्य समत्व को अपनाता है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। क्योंकि कर्मों का बंधन राग और द्वेष के कारण ही होता है, और समत्व इन दोनों को समाप्त कर देता है।

शरीर के प्रति अत्यधिक मोह भी सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधा है। यह शरीर नश्वर है और रोगों का घर है। जब तक मनुष्य इसे ही अपना सब कुछ मानता रहेगा, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब वह समझता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, तब उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है। यही परिवर्तन उसे सम्यक् दर्शन और ले जाता है।

कर्मों का सिद्धांत भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखें। क्योंकि जैसा हमारा चिंतन होगा, वैसा ही

हमारा जीवन बनेगा। यदि हमारे भाव शुद्ध और सम्यक् होंगे, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे और उनका फल भी शुभ होगा।

महत्त्व वस्तुओं का नहीं, बल्कि भावों का होता है। यदि किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में देने की भावना है, तो वह भी महान है। वहाँ यदि किसी के पास सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर दया और करुणा नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर अच्छे भावों को विकसित करें।

सम्यक्त्व का जागरण जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं, तब हमें वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यही सम्यक् दर्शन का सार है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सम्यक्त्व केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलित, शांत और सार्थक बना सकते हैं। जब हमारे भीतर सम्यक्त्व के भाव जागृत होते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांके, अपने विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की ओर उन्मुख हों। यही सम्यक्त्व की सच्ची साधना है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी।

कांतिलाल मांडोट

भारत के पुनर्जागरण की तथा-कथा, देश की सर्वांगीण प्रगति का मूल राष्ट्रीय जागरण

1947 में भारत एवं पाकिस्तान ने एक साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी किंतु पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा धारण कर अलग दिशा में आगे बढ़ता गया जिसके फलस्वरूप आज पाकिस्तान विपन्न और गरीब देश बन गया है। दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक अवधारणा की दिशा में नई-नई विकास के सोपनो को प्रतिपादित कर आगे बढ़ता गया। भारत वैश्विक स्तर पर सामरिक आर्थिक एवं अन्य विषयों पर काफी हद तक प्रगति प्राप्त कर चुका है।भारत ने आश्चर्यजनक रूप से देश को विकसित मजबूत एवं सशक्त बना दिया है।भारतीय परिदृश्य और संदर्भ में भारत में विगत एक दशक में व्यापक तथा आदुलत चूल परिवर्तन देखे गये हैं। राजनीतिक परिदृश्य में उत्तरदायित्व आधारित शासन प्रशासन-प्रणाली, सांस्कृतिक विमर्श में सनातनी सांस्कृतिक सभ्यता-गौरव को पुनर्प्राप्ति और आर्थिक नीतियों के संरचनात्मक सुधारों ने देश की दिशा और दशा तय की है। इन नई विचारधारा एवं रणनीति ने भारत को न केवल आंतरिक रूप से सशक्त किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

भारतीय राजनीति में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा परिवर्तन रिपोर्ट कार्ड राजनीति का उदय रहा, जिसमें आम जनता और राजनीतिक नेताओं और दलों का मूल्यांकन उनके किए गए कार्यों और परिणामों के आधार पर कसौटी पर कसा जाने लगा है।संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन केंद्र की सख्त और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा

विचारधारा का प्रतीक बना। तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीयता और शरणार्थी नीति में नई विचारों की श्रृंखला को जन्म दिया। भारत की परंपरागत लोकतांत्रिक विरासत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए नया संसद भवन, ई-संसद और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया तथा धनबल के प्रभाव ने लोकतांत्रिक विमर्श को चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भी बनाया गया है।

नये भारत की संकल्पना और अवधारणा को केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित परिसीमित नहीं रखा गया है बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यापक फलक पर भी इसका गहरा असर और परिणाम परिलक्षित हुए हैं। भारत की महान अर्वाचीन योग और आयुर्वेद जैसी अवधारणा को केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित परिसीमित नहीं रखा गया है बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यापक फलक पर भी इसका गहरा असर और परिणाम परिलक्षित हुआ है। भारत की महान अर्वाचीन योग और आयुर्वेद जैसी परंपरा को वैश्विक स्तर प्रचारित प्रसारित कर नई अवधारणा तथा पहचान प्रदान की गई है। अयोग्यता में राममंदिर निर्माण ने भारतीय परंपरा और धार्मिक-सांस्कृतिक आकांक्षाओं की विशाल अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों में भारतीय आख्यानों और इतिहास को नवीन स्वरूप देने के प्रयास किए गए हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पुष्पित पल्लवित करने के प्रयासों को संपूर्ण प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही, सांस्कृतिक कूटनीति नवीन अवधारणा के माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ रूप से विस्तारित की है। हालाँकि, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के

साथ अनेक कठिन एवं दुष्कर चुनौतियाँ भी रहीं हैं। बहुलतावाद और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उठते सवाल तथा परंपरा बनाम आधुनिकता की खींचतान समाज में गूढ विचार विमर्श का विषय बनी रही। आर्थिक पुनर्जागरण के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने इस दशक में उल्लेखनीय असर अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। जीएसटी (2017) ने कर संरचना को एकीकृत और पारदर्शी बनाया। जीएसटी को 2025 में 22 सितंबर से नवीन संशोधन कर एकदम सरल एवं स्पष्ट कर काफी हद तक सस्ता करने आम जन को बड़ी राहत पहुंचाई है। डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और एन ने वित्तीय समावेशन और नकदी रहित लेन-देन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए।

स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विदेशी निवेश वृद्धि, रेलवे और सड़क निर्माण में गति तथा बिजली और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार इस आर्थिक पुनर्जागरण के प्रमुख संकेतक रहे।इसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या, ग्रामीण-शहरी असमानता और आय-विभाजन जैसी बड़ी और गंभीर चुनौतियाँ भारत देश के आर्थिक परिदृश्य को संतुलित होने से रोकती रही हैं। कृषि सुधार अभी तक आधे अधूरे रह गए और हरियाणा पंजाब तथा अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलनों ने यह यह साफ तथा स्पष्ट संकेत दिया कि विकास की अवधारणा सबके लिए समान रूप से सुलभ नहीं है।

भारत ने पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान बनाई ग्लोबल साउथ के अधिकारों पर उठते सवाल तथा परंपरा बनाम आधुनिकता की खींचतान समाज में 2023 में आयोजित ह20 सम्मेलनों में भारत ने वैश्विक मुद्दों पर संतुलित और निर्णायक नेतृत्व प्रस्तुत किया। चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में 10 महत्वपूर्ण देशों के साथ 27 देशों ने भारत चीन और रूस पर अपना विश्वास जाहिर कर यूरोपीय शक्तियों एवं मनमानी का खुला विरोध किया है, जिसमें भारत पर अमेरिका द्वारा 50% लगाए गए टैरिफ का भी खुला विरोध हुआ है। रूस, चीन और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंधों ने भारत की स्थिति को और सशक्त मजबूत किया।पिछले दस वर्षों का भारत राजनीतिक दृढ़ता, सांस्कृतिक आत्मगौरव और आर्थिक समावेशन और नकदी रहित लेन-देन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए। सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने और आर्थिक संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रही। हालाँकि असमानता, बेरोजगारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी विकराल चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, फिर भी यह कहना उचित होगा कि यह दशक भारत के लिए राजनीतिक-सांस्कृतिक आर्थिक पुनर्जागरण का समय रहा है, जिसने भारत को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में निर्णायक शक्ति बना दिया है। वैश्विक की सनातनी सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारत की सामरिक शक्ति में इजाफा होकर पिछले दहक दशक में भारतीय जनमानस की एकजुटता एवं देश के नेतृत्व की कार्य कुशलता के परिणाम स्वरूप भारत का सम्मान और कद वैश्विक परिदृश्य में काफी हद तक ऊंचा हुआ है।

संजीव जक्जु

पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था: चुनावी उफान के बीच उठते सवाल

पश्चिम बंगाल में पिछले डेढ़ दशक से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार का शासन रहा है। वर्तमान समय में राज्य विधानसभा चुनावों का माहौल गर्म है, और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी तथा तनाव का बढ़ना स्वाभाविक भी माना जा सकता है। किंतु हाल ही में मालदा में घटी घटना जहाँ सात न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ द्वारा कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं ? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन जब यह विरोध हिंसक रूप ले ले और न्यायिक अधिकारियों जैसी संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तब यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासनिक विफलता का संकेत बन जाता है। इस घटना के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत की कड़ी प्रतिक्रिया भी इस बात को रेखांकित करती है कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी।

चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य है, परंतु कानून-व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरण से प्रभावित होंगे प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। साथ ही, राज्य में अवैध घुसपैट, मतदाता सूची में संशोधन (जैसे स्ट्रुक्चर प्रक्रिया) और पहचान से जुड़े मुद्दे भी समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। ये विषय न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रतिक्रिया भी इस बात को रेखांकित करती है कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी।

चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य है, परंतु कानून-व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरण से प्रभावित होंगे प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। साथ ही, राज्य में अवैध घुसपैट, मतदाता सूची में संशोधन (जैसे स्ट्रुक्चर प्रक्रिया) और पहचान से जुड़े मुद्दे भी समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। ये विषय न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रतिक्रिया भी इस बात को रेखांकित करती है कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी।

मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा वैश्विक संकट बन चुका है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, इस समय संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यहां से गुजरने वाले तेल और गैस की आपूर्ति पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव वैश्विक बाजार, महंगाई और आम जनजीवन पर पड़ता है।

हाल ही में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक में साठ से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसमें इस संकट को सुलझाने के उपायों पर विचार किया गया। इस बैठक में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे संकट का समाधान केवल बातचीत और शांति के माध्यम से ही संभव है। भारत का यह रुख उसकी पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें वह हमेशा संवाद, संयम और संतुलन को प्राथमिकता देता रहा है।

भारत द्वारा यह भी बताया गया कि इस संघर्ष में अब तक केवल भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। यह तथ्य इस संकट की गंभीरता को और बढ़ा देता है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध का प्रभाव सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह निर्दोष लोगों की जान भी लेता है। भारत का यह बयान सभी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी भी है कि यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम भी भयावह हो सकते हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस संघर्ष को अपनी रणनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिकी संकट द्वारा दिए गए बयान इस बात का संकेत देते हैं कि वे इस युद्ध को अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने बातचीत की बात भी की है, लेकिन उनके वक्तव्यों में कठोरता और चेतावनी का स्वर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार के विरोधाभासी संकेत



की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरण से प्रभावित होंगे प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। साथ ही, राज्य में अवैध घुसपैट, मतदाता सूची में संशोधन (जैसे स्ट्रुक्चर प्रक्रिया) और पहचान से जुड़े मुद्दे भी समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। ये विषय न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रतिक्रिया भी इस बात को रेखांकित करती है कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी।

होर्मुज संकट के बीच वैश्विक तनाव और संवाद की आवश्यकता, होरमुज संकट का समाधान बातचीत से ही सम्भव



स्थिति को और जटिल बना देते हैं।

इरान की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। उसने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उसके नियंत्रण में है और यह तभी खुलेगा जब उसकी शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। यह स्थिति को केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर तनाव को बढ़ाने वाली है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो तेल की आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है, जिससे विश्वभर में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है।

इस संघर्ष का एक और गंभीर पहलू मानवीय संकट है। विभिन्न देशों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल या विस्थापित हुए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह स्थिति दर्शाती है कि युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं होता, बल्कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगताना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और युद्धवियम की अपील की है। उनका मानना है कि यदि यह संघर्ष जारी रहा तो इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक मंदी, माछा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर होगा, क्योंकि वे पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जुझ रहे हैं।

भारत का रुख इस पूरे परिदृश्य में संतुलित और दूरदर्शी दिखाई देता है। उसने न तो किसी पक्ष का समर्थन किया है और न ही किसी के खिलाफ आक्रामक बयान दिए हैं। इसके बजाय

शिक्षक, शोध और शिक्षा - सबका नया केंद्र बनेगी एनसीईआरटी

[एनसीईआरटी अब किताबों की मेज से उठकर नीति की कुर्सी पर]
[एनसीईआरटी का डीएड यूनिवर्सिटी बनना क्यों है ऐतिहासिक फैसला]

जब किसी देश की शिक्षा व्यवस्था करवट लेती है, तो बदलाव केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। भारत की शिक्षा यात्रा में 2026 का आरंभ ऐसा ही एक निर्णायक पड़ाव बन गया है। पिछले 6 दशकों से करोड़ों विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से मार्ग दिखाने वाली एनसीईआरटी अब 'डीएड-टू-बी-यूनिवर्सिटी' बनने जा रही है। अब वह केवल किताबें तैयार करने वाली संस्था नहीं रहेगी, बल्कि डिग्री प्रदान करेगी, शोध को बढ़ावा देगी, नए शिक्षकों का निर्माण करेगी और शिक्षा की नई नीतियों की आधारशिला रखेगी। यह बदलाव महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भीतर तक बदल

देने वाली उस ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत है, जिसकी नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने रखी थी।

1961 में स्थापित एनसीईआरटी ने दशकों तक भारतीय विद्यालयी शिक्षा की आधारशिला बनकर कार्य किया। देश के अधिकांश स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धतियां इसी संस्था की दृष्टि से आकार लेती रहीं। इसकी किताबों ने गांव के छोटे विद्यालय से लेकर महानगरों के प्रतिष्ठित स्कूलों तक शिक्षा का एक समान आधार तैयार किया। लेकिन समय बदलने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि केवल पाठ्यपुस्तकें तैयार कर देना पर्याप्त नहीं है। नई शिक्षा व्यवस्था को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो शिक्षा को गहराई से समझें, उस पर शोध करें और बदलते समय के अनुसार उसे नया स्वरूप दे सकें। यही सोच एनसीईआरटी को विद्यालयी शिक्षा की सीमाओं से आगे बढ़ाकर उच्च शिक्षा के केंद्र में ले आई।

वर्ष 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

प्रधान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत दिया था कि एनसीईआरटी को शोध और शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। लगभग 3 वर्षों की तैयारी, विशेषज्ञों की सिफारिशों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद अब यह निर्णय अंतिम रूप लेने जा रहा है। दिल्ली स्थित एनसीईआरटी मुख्यालय के साथ-साथ अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के क्षेत्रीय संस्थान भी इस नए स्वरूप का हिस्सा बनेंगे। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि एनसीईआरटी का दायरा बढ़ेगा, बल्कि यह कि देश के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा और शोध के नए केंद्र उभरेंगे। पहली बार विद्यालयी शिक्षा और विश्वविद्यालयी शोध एक ही मंच पर साथ दिखाई देंगे।

डीएड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद एनसीईआरटी को व्यापक शैक्षणिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अब वह स्वतंत्र रूप से डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर तक के पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगा। शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल

विकास, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, बहुभाषी अध्ययन और शिक्षक-प्रशिक्षण जैसे विषयों में विशेष डिग्रियां दी जा सकेंगी। संस्था को अपने पाठ्यक्रम स्वयं बनाने, शैक्षणिक ऋण बैंक प्रणाली लागू करने और राष्ट्रीय संस्थानत रैंकिंग ढांचे में शामिल होने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसके साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, छात्र-शिक्षक आदान-प्रदान तथा नए परिसर खोलने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीईआरटी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक पहुंचाना होगा।

दुर्घकों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती रही है—एक ओर स्कूल, दूसरी ओर विश्वविद्यालय। विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री और विश्वविद्यालयों में होने वाला शोध शायद ही कभी एक-दूसरे से जुड़ पाए। परिणामस्वरूप शोध पुस्तकालयों और रिपोर्टों तक सीमित रह गया, जबकि स्कूल पुराने ढर्रे पर चलते रहे। एनसीईआरटी का यह नया रूप अब इस

दूरी को समाप्त करने वाला सशक्त सेतु बनेगा। जो विशेषज्ञ पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, वही शिक्षक गढ़ेंगे और वही शिक्षा पर शोध भी करेंगे। इससे नई खोजें और नए विचार सीधे कक्षा तक पहुंचेंगे। बच्चों की पढ़ाई अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकेगी।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हमेशा से प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षकों की कमी रही है। अनेक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान आज भी पुराने पाठ्यक्रमों और पारंपरिक तरीकों तक सीमित हैं। ऐसे समय में एनसीईआरटी का यह नया स्वरूप शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। अब वह ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा, जिनमें डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं और बहुभाषी अध्ययन जैसे आधुनिक विषय शामिल होंगे। क्षेत्रीय संस्थानों में पीजी और पीएचडी कार्यक्रम शुरू होने से युवा शोधकर्ताओं को विद्यालयी शिक्षा की

वास्तविक चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। उनके शोध के परिणाम सीधे पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा नीतियों में दिखाई देंगे, जिससे शिक्षा अधिक जीवंत, प्रभावी और समयानुकूल बन सकेगी।

हर बड़ा परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। एनसीईआरटी के सामने भी कई गंभीर प्रश्न हैं। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यूजीसी के नियमों के अधीन आने से उसकी स्वतंत्र कार्यशैली प्रभावित हो सकती है। जिस संस्था की पहचान अब तक विद्यालयी शिक्षा से रही है, उसके लिए विश्वविद्यालयी ढांचे में ढलना आसान नहीं होगा। नए विभाग, प्रशिक्षित सकाय, शोध सुविधाएं, पर्याप्त बजट और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उच्च शिक्षा की नई भूमिका निभाते हुए एनसीईआरटी अपनी मूल जिम्मेदारी, यानी स्कूल शिक्षा को मजबूत बनाने, से दूर न हो। यदि बजट, परादर्शिता और गुणवत्ता पर बराबर ध्यान

दिया गया, तो यही चुनौतियां उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं।

यदि यह परिवर्तन सफल हुआ, तो आने वाले समय में एनसीईआरटी केवल एक संस्था नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगी। एक ओर देश का विद्यार्थी उसकी किताबों से पढ़ेगा, दूसरी ओर उसी संस्था का शोधकर्ता नई शिक्षा नीति तैयार करेगा और वही शिक्षक गढ़े जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देंगे। यह ऐसा मॉडल होगा, जहां शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण एक-दूसरे से सीधे जुड़े होंगे। विकसित भारत का सपना केवल उद्योग, तकनीक और अर्थव्यवस्था से पूरा नहीं होगा; उसकी सबसे मजबूत आधारशिला शिक्षा ही बनेगी। एनसीईआरटी का यह नया स्वरूप उसी आधारशिला को अधिक मजबूत, व्यापक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

प्रो. आरके जैन 'अ्रिजीत '

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ल विजय लक्ष्मी नगर पराना खैरबाद तहसील व जनपद-सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीरोट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संचलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:-**उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I.NO. UPPHN/2009/34814 मोो 70 -95 1115 1254,E-Mail :- news@swatantraprabhat.com**

